प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

पुनर्विलोकन याचिका सं 24 /2025

1 – डी.के. चंदेल पिता पी.एल. चंदेल उम्र लगभग 60 वर्ष रायपुर, निवासी क्वार्टर नं. जी–8, पी.डब्ल्यू.डी. कॉलोनी, कटोरा तालाब, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।(उत्तरवादी सं. 5)

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा , छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

2– प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, अटल नगर, नवा रायपुर,छत्तीसगढ़.

3– अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।

4 – अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सर्कल नंबर 1, रायपुर, छत्तीसगढ़।

5 – निर्मल कुमार सिंह पिता श्री आधार सिंह ठाकुर 61 वर्ष, वर्तमान में कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रभाग बेमेतरा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ के रूप मे पदस्थ

..... उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता हेतु :–––श्री सुनील ओत्वानी तथा श्री शोभित कोष्टा,अधिवक्तागण

राज्य/उत्तरवादी संख्या 1 से 4 हेतु :––सुश्री नूपुर त्रिवेदी,पैनल अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 5 हेतु :श्री घनश्याम पटेल, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद

बोर्ड पर आदेश दिया

11/03/2025

1. यह पुनर्विलोकन याचिका उत्तरवादी संख्या 5 निर्मल कुमार सिंह द्वारा अपने स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.11.2024 के विरुद्ध दायर डब्ल्यूपीएस संख्या 7971/2024 में पारित दिनांक 6.12.2024 के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है। पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता डीके चंदेल इस आधार पर दिनांक 6.12.2024 के आदेश की पुनर्विलोकन की मांग कर रहे हैं कि निर्मल कुमार सिंह, उत्तरवादी संख्या 5 और डब्ल्यूपीएस संख्या 7971/2024 में याचिकाकर्ता ने महत्वपूर्ण तथ्यों को दबा दिया है और पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता की पीठ पीछे दिनांक 6.12.2024 का आदेश प्राप्त कर लिया है।

2. इस वर्तमान पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय लेने के लिए संक्षिप्त तथ्य यह है कि सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग ने दिनांक 30.11.2024 को स्थानांतरण आदेश जारी किया है, जिसके द्वारा पुनरीक्षण याचिकाकर्ता डी.के. चंदेल को लोक निर्माण विभाग, रायपुर से लोक निर्माण विभाग, बेमेतरा स्थानांतरित किया गया है, जबकि उत्तरवादी क्रमांक 5 निर्मल कुमार सिंह को प्रशासनिक आवश्यकता के कारण लोक निर्माण विभाग, बेमेतरा से लोक निर्माण विभाग, रायपुर स्थानांतरित किया गया है। उत्तरवादी क्रमांक 5 ने अपने स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी है और 6.12.2024 को जब डब्लूपीएस क्रमांक 7971/2024 सुनवाई के लिए आया, तो याचिकाकर्ता निर्मल कुमार सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता 30.6.2025 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त होने जा रहा है और केवल 7 माह शेष हैं, ऐसे में स्थानांतरण आदेश राज्य शासन की स्थानांतरण नीति के अनुरूप नहीं है।हालांकि, याचिकाकर्ता निर्मल कुमार सिंह ने इस तथ्य को छिपाया कि दिनांक 30.11.2024 के स्थानांतरण आदेश के अनुसरण में, वे पहले ही रायपुर में अपने स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं और उन्होंने यह भी गलत बयान दिया है कि वर्ष 2022 से संबंधित स्थानांतरण नीति अस्तित्व में है। इस न्यायालय ने केवल इस आधार पर कि निर्मल कुमार सिंह 30.6.2025 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और आगे 2022 की स्थानांतरण नीति के अनुसार यदि कोई कर्मचारी एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने जा रहा है तो स्थानांतरण पर प्रतिबंध है, निर्मल कुमार सिंह की रिट याचिका को अनुमति दी।पुनर्विलोकन के याचिकाकर्ता डी.के. चंदेल, जिन्हें याचिकाकर्ता निर्मल कुमार सिंह द्वारा दायर डब्ल्यूपीएस संख्या 7971/2024 में उत्तरवादी संख्या 5 के रूप में रखा गया था, पर इस न्यायालय का ध्यान नहीं गया और डब्ल्यूपीएस संख्या 7971/2024 में किए गए प्रस्तुतीकरण तथा उस रिट याचिका में अनुलग्नक पी7 के रूप में संलग्न स्थानांतरण नीति पर भरोसा करते हुए, रिट याचिका को अनुमति देते हुए दिनांक 6.12.2024 का आदेश पारित किया।यहां इस तथ्य का उल्लेख करना उचित है कि वर्तमान पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता डी.के. चंदेल ने रिट अपील संख्या 10/2025 में दिनांक 6.12.2024 के आदेश को चुनौती दी थी और इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने दिनांक 16.1.2025 के आदेश के तहत रिट अपील को वापस लेते हुए खारिज कर दिया था, हालांकि, वर्तमान पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता डी.के. चंदेल को समीक्षा याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी क्योंकि उन्हें दिनांक 6.12.2024 के आदेश पारित करने से पहले नोटिस नहीं दिया गया था तथा वर्तमान पुनर्विलोकन याचिका दायर की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता डी.के. चंदेल की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निर्मल कुमार सिंह, जो डब्ल्यूपीएस संख्या 7971/2024 में याचिकाकर्ता थे, ने इस तथ्य को दबा दिया है कि वर्ष 2022 की स्थानांतरण नीति का कोई अस्तित्व नहीं है।उक्त स्थानांतरण नीति दिनांक 12.8.2022 केवल एक वर्ष की अवधि के लिए थी तथा दूसरी बात यह कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता डी.के. चंदेल दिनांक 3.12.2024 को कार्यभार ग्रहण करते हुए बेमेतरा में अपने स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। हालांकि निर्मल कुमार सिंह द्वारा डब्ल्यूपीएस क्रमांक 7971/2024 में उक्त तथ्य नहीं लाया गया तथा दिनांक 6.12.2024 के आदेश पारित होने के पश्चात उन्होंने दिनांक 9.12.2024 को पुनः बेमेतरा में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार निर्मल कुमार सिंह ने न्यायालय को गुमराह किया है तथा तथ्यों को दबाते हुए दिनांक 6.12.2024 का आदेश अपने पक्ष में प्राप्त कर लिया है।**रामजस फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य**, (2010) 14 एससीसी 38 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया गया।

4. उत्तरवादी संख्या 5 निर्मल कुमार सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम प्रति पर प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा कोई भी भौतिक तथ्य नहीं छिपाया गया है और इस आधार पर कि याचिकाकर्ता 30.6.2025 को सेवानिवृत्त होने जा रहा है, जो उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से सिर्फ 7 महीने दूर है और आगे स्थानांतरण नीति 2022 के अनुसार, जिसमें उनका सद्भावनापूर्वक विश्वास है कि यह अभी भी अस्तित्व में है, उन्होंने डब्ल्यूपीएस संख्या 7971/2024 में अपना प्रस्तुतीकरण किया और इस प्रकार उत्तरवादी संख्या 5 निर्मल कुमार सिंह किसी भी तथ्य को दबाने या किसी भी गलत बयानी के लिए दोषी नहीं हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सब कुछ सद्भावनापूर्वक किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा बहुत सावधानी के साथ अभिलेख का अध्ययन किया है।

6. यह सत्य है कि उत्तरवादी सं. 5 निर्मल कुमार सिंह 30.6.2025 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, हालांकि, यह भी उतना ही सत्य है कि स्थानांतरण नीति 2022 अस्तित्व में नहीं थी, जो किसी भी कर्मचारी के स्थानांतरण को प्रतिबंधित करती है जो उसके स्थानांतरण आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने जा रहा है, लेकिन, कहा गया स्थानांतरण नीति 2022 अस्तित्व में नहीं है, उत्तरवादी सं. 5 निर्मल कुमार सिंह के विद्वान वकील द्वारा जानबूझकर नहीं कहा गया है और निर्मल कुमार सिंह के पक्ष में आदेश सुरक्षित करने के लिए दस्तावेज़ को डब्ल्यूपीएस संख्या 7971/2024 के साथ संलग्न किया गया था, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि स्थानांतरण नीति 2022 केवल एक वर्ष के लिए है और इस उत्तरवादी सं. 5 निर्मल कुमार सिंह ने इस न्यायालय के साथ रिष्टि कारित किया है और वह इस न्यायालय में साफ हाथों से नहीं आए हैं, जो कि न्यायालय से अनुतोष पाने के लिए एक पवित्र कार्य है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रामजस मामले में निम्नानुसार निर्णय दिया है:------

"21. यह सिद्धांत कि जो व्यक्ति साफ-सुथरे हाथों से न्यायालय में नहीं आता है, वह अपने परिवाद के गुण-दोष के आधार पर सुनवाई का हकदार नहीं है और किसी भी मामले में ऐसा व्यक्ति किसी अनुतोष का हकदार नहीं है, यह न केवल संविधान के अनुच्छेद 32, 226 और 136 के तहत दायर याचिकाओं पर लागू होता है,

बल्कि अन्य न्यायालय और न्यायिक मंचों में शुरू किए गए मामलों पर भी लागू होता है। इस सिद्धांत में अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि प्रत्येक अदालत न केवल हकदार है, बल्कि बेईमान वादियों से स्वयं को बचाने के लिए बाध्य है, जिनके मन में सत्य के लिए कोई सम्मान नहीं है और जो झूठ का सहारा लेकर या गलत बयान देकर या तथ्यों को दबाकर न्याय की धारा को प्रदूषित करने की कोशिश करते हैं, जिनका मामले में उठने वाले विवाद्यक के न्यायनिर्णयन पर असर पड़ता है।27. अपील पर, लॉर्ड कोजेंस–हार्डी, एम.आर. और वॉरिंगटन, एल.जे. ने डिवीजनल कोर्ट द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को मंजूरी दी। स्क्रटन, विद्वान न्यायाधीश जो इस बात से सहमत थे कि अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए, ने टिप्पणी की:(आर. बनाम केंसिंग्टन आयकर आयुक्त, (1917) 1 केबी 486 (सीए), केबी पृ. 514)

".....और यह कई वर्षों से न्यायालय का नियम रहा है, और जिसे बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है, कि जब कोई आवेदक एकपक्षीय बयान पर राहत प्राप्त करने के लिए न्यायालय में आता है, तो उसे सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का पूर्ण और निष्पक्ष खुलासा करना चाहिए – तथ्य, विधि नहीं है। यदि वह मदद कर सकता है तो उसे विधि को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, न्यायालय को विधि का ज्ञान होना चाहिए। परंतु वह तथ्यों के बारे में कुछ नहीं जानता है, और आवेदक को तथ्यों को पूरी तरह और निष्पक्ष रूप से बताना होगा, और जिस दंड के द्वारा न्यायालय उस दायित्व को लागू करता है वह यह है कि यदि उसे पता चलता है कि तथ्य पूरी तरह और निष्पक्ष रूप से उसके समक्ष नहीं बताए गए हैं, तो न्यायालय अपूर्ण कथन के आधार पर की जाने वाली किसी भी कार्यवाही को अपास्त कर देगा.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. उपर्युक्त नियम इस न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में मामलों में ऐसे पक्ष को राहत देने से इंकार करने के लिए लागू किए गए हैं जिनका आचरण दोषपूर्ण है और जो न्यायालय में साफ हाथों से नहीं आया है – हरि नारायण बनाम बद्री दास, एआईआर 1963 एससी 1558, वेलकम होटल बनाम एपी राज्य, (1983) 4 एससीसी 575, जी नारायणस्वामी रेड्डी बनाम कर्नाटक सरकार, (1991) 3 एससीसी 261, एस.पी. चेंगलवरैया नायडू बनाम जगन्नाथ, (1994) 1 एससीसी 1, एवी पपय्या शास्त्री बनाम एपी सरकार, (2007) 4 एससीसी 221, प्रेस्टीज लाइट्स लिमिटेड बनाम एसबीआई, (2007) 8 एससीसी 449, सुनील पोद्दार शर्मा बनाम सेल, (2008) 12 एससीसी 481, जी. जयश्री बनाम भगवानदास एस. पटेल, (2009) 3 एससीसी 141 और दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2010) 2 एससीसी 114।

29. अंतिम उल्लेखित निर्णय में, न्यायालय ने ऐसे मामलों की संख्या में वृद्धि पर दुख व्यक्त किया, जिनमें पक्षकारों ने झूठे और/या भ्रामक बयान देकर या सुसंगत तथ्यों को दबाकर या अपने पक्ष में आदेश पारित करने में न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास करके न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का प्रयास किया है और टिप्पणी की:(दलीप सिंह मामला, (2010) 2 एससीसी 114, एससीसी पृ. 116–17, कंडिका 1–2)

"1.कई शताब्दियों तक भारतीय समाज ने जीवन के दो बुनियादी मूल्यों को संजोया है, अर्थात सत्य' और 'अहिंसा'। महावीर, गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी ने लोगों को इन मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए मार्गदर्शन किया। सत्य न्याय वितरण प्रणाली का एक अभिन्न अंग था जो स्वतंत्रता–पूर्व युग में

प्रचलित था और लोग परिणामों की परवाह किए बिना न्यायालय में सच बोलने में गर्व महसूस करते थे। हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद की अवधि में हमारे मूल्य प्रणाली में भारी बदलाव देखा गया है।हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद की अवधि में हमारे मूल्य प्रणाली में भारी बदलाव देखने को मिले हैं। भौतिकवाद ने पुराने लोकाचार को पीछे छोड़ दिया है और व्यक्तिगत लाभ की चाह इतनी तीव्र हो गई है कि मुकदमेबाजी में शामिल लोग अदालती कार्यवाही में झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को दबाने का सहारा लेने में संकोच नहीं करते हैं।

2. पिछले 40 वर्षों में वादियों का एक नया पंथ उभरा है। इस पंथ के लोग सत्य के प्रति कोई सम्मान नहीं रखते है। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेशर्मी से झूठ और अनैतिक साधनों का सहारा लेते हैं। वादियों के इस नए पंथ द्वारा प्रस्तुत चुनौती का सामना करने के लिए, न्यायालयों ने समय-समय पर नए नियम विकसित किए हैं और अब यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जो वादी न्याय की धारा को प्रदूषित करने का प्रयास करता है या जो न्याय के शुद्ध स्रोत को कलंकित हाथों से छूता है, वह अंतरिम या अंतिम किसी भी अनुतोष का हकदार नहीं है।"

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरि नारायण बनाम बद्री दास के मामले में एआईआर 1963 एससी 1558 में कंडिका 9 में यह अभिनिर्धारित किया है किः

"9. .....ऐसा हो सकता है, लेकिन तथ्य अभी भी बना हुआ है कि दो महत्वपूर्ण बयान, जो यदि सत्य होते, तो अपीलकर्ता को धारा 13(1)(ए) के तहत संरक्षण प्राप्त करने में काफी सहायता कर सकते थे, यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा उस धारा पर रखे गए निर्माण पर भी, असत्य पाए गए हैं, और हमारी राय में, यह याचिका में ही एक बहुत गंभीर दुर्बलता है।यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विशेष अनुमति के लिए आवेदन में महत्वपूर्ण बयान देने और आधार स्थापित करने में सावधानी बरती जानी चाहिए कि कोई भी बयान गलत, असत्य या भ्रामक न हो।विशेष अनुमति के लिए आवेदनों से निपटने में, न्यायालय स्वाभाविक रूप से याचिकाओं में निहित तथ्यों के बयानों और तथ्य के आधारों को उनके अंकित मूल्य पर लेता है और ऐसे बयान देकर न्यायालय के विश्वास को धोखा देना अनुचित होगा जो असत्य और भ्रामक हैं।इसीलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता को दी गई विशेष अनुमति रद्द की जानी चाहिए। तदनुसार, विशेष अनुमति रद्द की जाती है और अपील खारिज की जाती है। अपीलकर्ता उत्तरवादी की लागत का भुगतान करेगा।"

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जी. नारायणस्वामी रेड्डी (मृत) एलआर और अन्य बनाम कर्नाटक सरकार और अन्य के मामले में, एआईआर 1991 एससी 1726 में रिपोर्ट किए गए पैरा 2 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

"2. .....16-17 दिसंबर, 1987 को संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें इस आधार पर अधिग्रहण को चुनौती दी गई कि निर्धारित समय के भीतर पंचाट नहीं दिए गए थे।इन दो रिट याचिकाओं में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उक्त भूमि के अधिग्रहण के संबंध में आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।इन याचिकाओं को उस उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

न्यायाधीश ने 29 नवंबर, 1988 को खारिज कर दिया था।एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा 6 अक्टूबर, 1989 को खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने उस उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले के खिलाफ ये विशेष अनुमति याचिकाएं, अर्थात् एस.एल.पी. संख्या 823 और 824/1990 दायर कीं और उनमें बेदखली पर अंतरिम रोक प्राप्त की। स्थगन आदेशों का अंतिम प्रभाव जो भी हो, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11–ए के प्रावधानों के तहत, जिसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, यह विवाद से परे है कि स्थगन आदेशों का तथ्य इन विशेष अनुमति याचिकाओं के निर्धारण में अत्यधिक महत्वपूर्ण था।काफी रोचक बात यह है कि विशेष अनुमति याचिकाओं में किसी भी स्थगन आदेश का कोई संदर्भ नहीं है और हमें इन आदेशों के बारे में तभी पता चला जब प्रतिवादी नोटिस के जवाब में उपस्थित हुए और अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया। हमारे विचार में, उक्त अंतरिम आदेशों का उठाए गए प्रश्न पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इसका खुलासा न करना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाने के समान है।केवल इसी आधार पर, विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य हैं।विधि में यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत राहत विवेकाधीन है और इस तरह की राहत के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ता को तथ्यों का स्पष्ट और पूर्ण खुलासा करना चाहिए।यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाता है, तो उसका आवेदन खारिज किया जा सकता है। हम तदनुसार विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करते हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इसी प्रकार, **डॉ. बुद्धि कोटा सुब्बाराव बनाम वी.के. परासरन एवं अन्य के मामले में, जो एआईआर 1996 एससी 2687 में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:**

"11. .....अभिलेख पर कोई "प्रथम दृष्टया" सामग्री नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उत्तरवादी संख्या 1 या उत्तरवादी संख्या 2 ने "झूठा साक्ष्य" दिया या न्यायालय में "झूठा" या "गढ़ा हुआ" साक्ष्य पेश किया। आवेदक के प्रस्तुतीकरणों पर विचार करते हुए, उनके मूल तत्वों को छोड़कर, तथ्यात्मक मैट्रिक्स जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, धारा 191, 192 या 193, एल.पी.सी. के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करते हैं। वर्तमान आवेदन का दायर किया जाना हमें इस न्यायालय द्वारा 16–3–1993 को आपराधिक अपील संख्या 275–277/1993 का निर्णय लिए जाने और तीन वर्ष से अधिक समय पहले पुनर्विलोकन याचिका को भी खारिज किए जाने के बाद भी मामले को "पुनः खोलने" का प्रयास प्रतीत होता है। न्यायिक कार्यवाही के किसी चरण में अंतिमता अवश्य जुड़ी होनी चाहिए। आवेदक द्वारा अपनाया गया तरीका अनुचित है तथा उसका आवेदन कानून और तथ्यों की गलत धारणा पर आधारित है।किसी भी वादी को अपने मामलों को अपनी इच्छानुसार निपटाने के लिए न्यायालय के समय और सार्वजनिक धन का असीमित दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है। न्याय तक आसान पहुंच का दुरुपयोग गलत या तुच्छ याचिका दायर करने के लाइसेंस के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।बार में प्रस्तुत किए गए निवेदनों तथा आवेदन के ज्ञापन में निहित निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, हम इस राय

पर पहुंचे हैं कि यह आवेदन गलत है, असमर्थनीय है तथा इसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है। तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।"

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के.डी. शर्मा बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य के मामले में (2008) 12 एससीसी 481 में पैरा 26 एवं 28 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

"26. यह सुस्थापित है कि "धोखाधड़ी सभी न्यायिक कृत्यों, चर्च संबंधी या लौकिक" से बचती है, इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड कोक ने लगभग तीन शताब्दियों पहले घोषणा की थी। अधिवक्ता द्वारा बनाम जगन्नाथ □ के एक प्रमुख निर्णय का संदर्भ दिया गया था जिसमें उपरोक्त टिप्पणियों को उद्धृत करते हुए, इस न्यायालय ने माना था कि एस.पी. चेंगलवरैया नायडू में इस न्यायालय द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त निर्णय/डिक्री को प्रत्येक न्यायालय द्वारा अमान्य माना जाना चाहिए।

28. जहां तक कानून के प्रस्ताव का संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने भी उपरोक्त निर्णयों और कई अन्य निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों पर विवाद नहीं किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, उपरोक्त मामलों में निर्धारित अनुपात लागू नहीं होता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय ईपीएफ स्टाफ फेडरेशन बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1629 में रिपोर्ट किए गएकंडिका 4 में अभिनिर्धारित किया गया है किः

"4. 20 मार्च, 2024 और 25 अप्रैल, 2024 के आदेशों को चुनौती देने वाली वर्तमान विशेष अनुमति याचिकाएँ 14 जून, 2024 को दायर की गई थीं। दिल्ली उच्च न्यायालय की वेबसाइट से पता चलता है कि 3 मई, 2024 को याचिकाकर्ता ने याचिका की शीघ्र सुनवाई के लिए सीएम आवेदन संख्या 26033/2024 के रूप में एक आवेदन पेश किया। यह स्पष्ट था कि शीघ्र सुनवाई के लिए प्रार्थना की गई थी क्योंकि अंतरिम राहत से इनकार कर दिया गया था और सितंबर, 2024 में एक लंबी तारीख तय की गई थी। उक्त आवेदन पर पारित 3 मई, 2024 के आदेश से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने कुछ समय तक मामले पर बहस करने के बाद उक्त आवेदन पर जोर नहीं दिया और इसलिए उसे खारिज कर दिया गया। इसलिए, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामले को 5 सितंबर, 2024 को सूचीबद्ध किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन विशेष अनुमति याचिकाओं में, जो 14 जून, 2024 को दायर की गई हैं, सीएम आवेदन संख्या 26033/2024 दाखिल करने के तथ्य को दबा दिया गया और यहां तक कि उक्त आवेदन पर पारित 3 मई, 2024 के आदेश को भी दबा दिया गया।"

12. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के. जयराम और अन्य बनाम बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी और अन्य के मामले में (2022) 12 एससीसी 815 में रिपोर्ट की गई कंडिका 10 और 14 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"10. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अधिकार क्षेत्र असाधारण, न्यायसंगत और विवेकाधीन है और यह अनिवार्य है कि रिट न्यायालय में आने वाला याचिकाकर्ता साफ–सुथरे हाथों से आए और बिना कुछ छिपाए या दबाए सभी तथ्य न्यायालय के सामने रखे जाये।एक वादी वाद से संबंधित सभी तथ्यों को बताने के लिए बाध्य है।यदि वह दूसरे पक्ष पर लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण या प्रासंगिक सामग्री को छिपाता है तो वह न्यायालय के साथ–साथ विपरीत पक्षों के साथ भी धोखाधड़ी करने का दोषी होगा जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।14. एक ही विषय–वस्तु से संबंधित कार्यवाहियों की बहुलता की जांच करने के लिए और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि झूठा बयान देने के दायित्व से बचने के लिए या तो चुप रहकर या दलीलों में भ्रामक बयान देकर भौतिक तथ्यों को दबाकर विभिन्न न्यायिक मंचों के माध्यम से असंगत आदेश प्राप्त करने के खतरे को रोकने के लिए, पक्षों को विवाद के विषय–वस्तु के किसी भी हिस्से के संबंध में सभी कानूनी कार्यवाहियों और वादो का विवरण प्रकट करना होगा, चाहे वे अतीत में हों या वर्तमान में, जो उनके ज्ञान में हैं। यदि विवाद के पक्षों के अनुसार, कोई कानूनी कार्यवाही या न्यायालयीन वाद लंबित नहीं था या नहीं है, तो उन्हें कानून के अनुसार पक्षों के बीच विवाद को हल करने के लिए अपने तर्क में अनिवार्य रूप से ऐसा बताना होगा।"

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अमर सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य (2011) 7 एससीसी 69 के मामले में पैरा 57 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"57. इस सिद्धांत को कायम रखने वाले सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक में, अपील न्यायालय में आर. बनाम केंसिंग्टन आयकर आयुक्त, पूर्व 11 प्रिंसेस डी पोलिग्नाक [(1917) 1 केबी 486 (सीए)] के.बी. स्क्रूटन, एल.जे. ने निम्न प्रकार से सूत्रबद्ध किया:

".....और यह कई वर्षों से न्यायालय का नियम रहा है, और जिसे बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है, कि जब कोई आवेदक एकपक्षीय बयान पर राहत प्राप्त करने के लिए न्यायालय में आता है, तो उसे सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का पूर्ण और निष्पक्ष खुलासा करना चाहिए–तथ्य, कानून नहीं। यदि वह ऐसा कर सकता है तो उसे कानून को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए–न्यायालय को कानून का ज्ञान होना चाहिए। परंतु उसे तथ्यों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और आवेदक को तथ्यों को पूरी तरह और निष्पक्ष रूप से बताना चाहिए, और जिस दंड के द्वारा न्यायालय उस दायित्व को लागू करता है वह यह है कि यदि उसे पता चलता है कि तथ्य पूरी तरह और निष्पक्ष रूप से उसके सामने नहीं बताए गए हैं, तो न्यायालय किसी भी कार्रवाई को रद्द कर देगा जो उसने अपूर्ण बयान के आधार पर की है। "

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 5 निर्मल कुमार सिंह ने जानबूझकर स्थानांतरण नीति 2022 के अस्तित्व और प्रयोज्यता के बारे में भौतिक तथ्यों को दबा दिया है, जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। निर्मल कुमार सिंह ने स्थानांतरण नीति 2022 के संबंध में एक तर्क दिया है और केवल अपने पक्ष में आदेश प्राप्त करने के लिए जानबूझकर उक्त दस्तावेज दायर किया है। उन्होंने इस तथ्य को भी छिपाया है कि स्थानांतरण आदेश पारित होने के बाद, वह अपने स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं और इस प्रकार उन्होंने इस न्यायालय को गुमराह

किया है जो वास्तव में न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग है। उन्हें मामले के वास्तविक तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहिए था और सभी सामग्रियाँ प्रस्तुत करनी चाहिए थीं ताकि यह न्यायालय मामले के संपूर्ण पहलू की सराहना करते हुए आदेश पारित कर सके।उन्होंने इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका में पारित दिनांक 6.12.2024 के आदेश के आधार पर कार्यभार ग्रहण किया है, जिस पर भी सद्भावपूर्वक कार्रवाई नहीं की गई है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अधिकार असाधारण, न्यायसंगत और विवेकाधीन है और यह अनिवार्य है कि रिट न्यायालय में आने वाला याचिकाकर्ता साफ हाथों से आए और बिना कुछ छिपाए या दबाए सभी तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखना चाहिए।एक वादी उन समस्त तथ्यों को बताने के लिए बाध्य है जो वाद से संबंधित हैं।यदि वह दूसरे पक्ष पर लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण या प्रासंगिक सामग्री को रोक लेता है तो वह न्यायालय के साथ–साथ विपक्षी पक्षों के साथ भी धोखाधड़ी करने का दोषी होगा, जिसे सहन नहीं किया जा सकता है।

15. तदनुसार, इस न्यायालय का विचार है कि प्रतिवादी संख्या 5 निर्मल कुमार सिंह द्वारा भौतिक तथ्यों को दबाना एक कदाचार है और केवल इसी कारण से वर्तमान समीक्षा याचिका 25,000/– रुपये की लागत के साथ अनुमति देने योग्य है, जिसे उत्तरवादी संख्या 5 निर्मल कुमार सिंह द्वारा वहन किया जाना है। निर्मल कुमार सिंह को इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष 25,000/– रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है और यदि उक्त राशि उनके द्वारा उक्त अवधि के भीतर रजिस्ट्री के समक्ष जमा नहीं की जाती है तो रजिस्ट्री को कानून के अनुसार उक्त राशि वसूलने के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. उपर्युक्त चर्चा के तहत पुनर्विलोकन याचिका को अनुमति दी जाती है। डब्ल्यूपीएस संख्या 7971/2024 में पारित दिनांक 6.12.2024 के आदेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।उत्तरवादी प्राधिकारियों को दिनांक 30.11.2024 के स्थानांतरण आदेश को निष्पादित करने तथा पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता डी.के. चंदेल को बेमेतरा में उनके स्थानांतरित पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराने तथा उत्तरवादी क्रमांक 5 निर्मल कुमार सिंह को रायपुर में उनके स्थानांतरित पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराने के लिए तत्काल कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

17. उपरोक्त टिप्पणियों तथा निर्देशों के साथ, पुनर्विलोकन याचिका की अनुमति दी जाती है।सही/–

सही/–

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur